



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1992/ज्येष्ठ 4, 1914

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1992/JYAISTHA 4, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

पधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 1992

धाय-कर

क्रा. प्रा. 357 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड धाय-कर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, धाय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धाय-कर (दसवां संशोधन)
नियम, 1992 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1991 से लागू समझे जाएंगे।

2. धाय-कर नियम, 1962 में, नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित
नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“6क. धारा 43 के उपबंध प्रत्येक लोक वित्तीय संस्था, मनुसूचित
बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विनिर्माण निगम की दशा

में, वहाँ लागू होंगे जहाँ ध्याज के रूप में उरकी धाय, डूबन और गंकास्य
शृणों के निम्नलिखित प्रयोगों के संबंध में है, अर्थात् :—

(क) (i) प्रथम या अटके हुए शृण अर्थात् जहाँ उपबंध (ii) में
विनिर्दिष्ट प्रकृति की अनियमितताओं, उधार लेने वालों के लेखाओं
में छह मास और उससे अधिक की अवधि के लिए ध्यान में
आती हैं और जहाँ लेखाओं के विनियमन की न्यूनतम
संभावनाएं नहीं हैं या जहाँ लेखाओं प्रकृति ऐसे लेखाओं की
बाबत निम्न प्रकार की कृपता के औपचारिक लक्षण प्रदर्शित
होते हैं, जैसे :—

1. धीमे या नग्न्य प्राप्त के परिणामस्वरूप कारबार में आभासी
असरोध;

2. अध्यापन के लिए लगातार असरोध करना या लेखा में निधियों
की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना बैंक जारी करना;

3. ऋय किए गए बिल या मितिकटे के भुगतान तीन मास और
उससे अधिक के लिए अतिशोध्य रहते हैं या ऐसे बिम्बों की वसूली में
उधार लेने वाले कठिनाइयां उत्पन्न करता हैं;

4. ऐसे साधन शृणों, किस्मों की दशा में जो छह मास या उससे
अधिक की अवधि से अनिर्णीत हैं;

5. बैंक द्वारा अशेषित वित्तीय या अर्धवार्षिक प्रचालन विवरण या स्टॉक विवरण अथवा तुल्यवस्तु और अन्य जानकारी देने में उधार लेने वाले द्वारा अप्रसन्न बिलम्ब;

6. निरीक्षण के दौरान अवलोकित स्टॉक का धीमा संबलन या अवरोध;

7. कारखाने के निरीक्षण या निरीक्षण अथवा बंद करने के दौरान अवलोकित क्रियाकलापों का कम या नमन्य स्तर;

8. मुख्य आवश्यकताओं जैसे दस्तावेजों का निष्पादन, जब अवलोकित अतिरिक्त प्रतिभूति देने का अनुपालन करने में लगातार बिलम्ब या ऐसी परिस्थितियों का अनुपालन न करना;

9. सहयोगी एककों को निधियों का उपयोग या कारखाने से प्राप्त पूर्ण प्रतिभूति का अर्जन अथवा धार लेने वाले द्वारा अपेक्षित रूप से बढ़ी रकम निकाला जाना;

10. परियोजना के कार्यक्रम से आशयित अनुमंजित जिसके कारण लागत में भारवान् वृद्धि होती है और अतिरिक्त मासिक बिल की अपेक्षा होती है;

11. समापन पर दबाव जिसके कारण कर्मचारियों की मजदूरी या कानूनी शोधों अथवा कार्यालय और कारखाने के परिसर के किराये का संदाय न करना;

12. बालू धारितियों से अधिक बालू दायित्व;

13. उधार लेने वालों के लेखा परीक्षकों द्वारा अवलोकित कोई बारी अनिश्चितता जिसका सुधार किया जाना बाकी है;

14. एकक के वित्तीय विवरणों द्वारा परकटित प्राथमिक कमजोरी उदाहरणार्थ एक साल के बाद लगातार रोकड़ा हानि।

(ii) उधार लेने वालों के लेखाओं में उपबंध (i) में निर्दिष्ट अनिश्चितताएं निम्नलिखित हैं:—

1. जहां लेखाओं से, अस्थायी अवधि के लिये आहरण शक्ति या मंजूर की गई सीमा से अधिक अध्यादान;

2. साधन हानि की बावत किन्हीं छह मास में अग्रपूत के लिये अतिशोध्य हैं या प्रत्यक्ष के अर्थात् आयात बिलों अथवा आस्थगित संदाय के अर्थात् किन्हीं तीन मास से अग्रपूत के लिये अतिशोध्य रहती हैं;

3. क्रय किये गये बिलों में कुल बकाया का 10% से 15% से अधिक बिल या उधार लेनेवाले के मितिकटे लेखा तीन मास से अग्रपूत अवधि के लिये संदाय के लिये अतिशोध्य हैं और असंदत बिलों के संबंध में प्रत्यापन तुरन्त नहीं हो रहा है।

(ख) वापस लिये गये अग्रिम, अर्थात् जहां प्रतिदाय अतिशक्य हो और एकक को पुनःप्रवर्तित करना उचित नहीं समझा जाता हो और अग्रिमों को वापस लेने के लिये निर्णय ले लिया गया हो।

(ग) वाद फाइल किये गये लेखा अर्थात् जहां विधिक कार्रवाई या बसूली कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं और अग्रिम की बसूली के लिये वाद सम्बन्धित है।

(घ) डिफ़ॉल्ट ग्रेण, अर्थात् जहां वाद फाइल कर दिये गये हैं और डिफ़ॉल्ट प्राप्त कर ली गई है तथा ऐसी डिफ़ॉल्ट निष्पादन के लिये सम्बन्धित है।

(ङ) उनके ऋणों की बसूली, प्रतिभूति, की कीमत में हुई कमी, प्रतिभूतियों को प्रवृत्त करने और निर्योक्त करने में कठिनाई, या उधार लेने वालों की बैंक की शोध रकमों को मागत: या पूर्णतः प्रतिदाय करने में अशक्तता

अथवा अनिच्छा के कारण नकारात्मक हो रही है और ऐसे ऋणों को पूर्णगामी खंड (क) से (घ) में सम्मिलित नहीं किया गया है।"

[नं. 9029/का.सं. 142/29/91-टीपीएल (भाग)]
अखिलेश प्रसाद, निदेशक (टीपीएल-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 357(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall be deemed to come into force the 1st day of April, 1991.

2. In the Income-tax Rules, 1962,

after rule 6E, the following rule shall be inserted, namely :—

"6EA. The provisions of section 43D shall apply in the case of every public financial institution, scheduled bank, State financial corporation and State industrial investment corporation where its income by way of interest pertains to the following categories of bad and doubtful debts, namely :—

(a)(i) Non-viable or sticky advances, [i.e., where irregularities of the nature specified in sub-clause (ii) are noticed in the accounts of the borrowers for a period of six months and more and there are no minimum prospects of regularisation of accounts, or where the accounts or information in relation to such accounts reflect usual signs of sickness, such as,—

1. apparent stagnation in the business as a result of the slow or negligible turnover ;

2. frequent requests for over-drawing or issue of cheques without ensuring availability of funds in the account;

3. bills purchased or discounted remain overdue for 3 months and more or the recovery of such bills from the borrower poses difficulties ;

4. in the case of term-loans, instalments which are overdue for 6 months or more;

5. unexplained delays by the borrower in submission of quarterly or half-yearly operating statements or stock statements or balance sheets and other information required by the bank;

6. slow movement or stagnation of stocks observed during inspections ;

7. low or negligible level of activity observed during inspections or suspension or closure of the business;

8. persistent delay in compliance with vital requirements like execution of documents, producing additional security when required or non-compliance with such requirements;
 9. diversion of funds to sister units or acquiring capital assets not relevant to the business or large personal withdrawals by the borrowers;
 10. international non-adherence to project schedules leading to substantial cost escalations and requirement of additional term-finance.
 11. the pressure on the liquidity leading to non-payment of wages to workers or statutory dues or rents of office and factory premises;
 12. the current liabilities exceeding current assets;
 13. any grave irregularities observed by the auditors of the borrowers which remain to be rectified;
 14. basic weakness revealed by the financial statements of the unit, for example, continued cash loss beyond one year.
- (ii) The irregularities referred to in sub-clause (i) in the accounts of the borrowers are,—
1. where the accounts are over-drawn beyond the drawing power or the sanctioned limit, for a temporary period;
 2. instalments in respect of term loan are overdue for less than 6 months or import bills under letters of credit or instalments under deferred payment carried are over due for less than 3 months;
 3. bills not exceeding 10 per cent to 15 per cent of the total outstandings in the bills purchased or discounted account of the borrower are overdue for payment for a period of less than 3 months and refund in respect of unpaid bills is not forthcoming immediately.]
 - (b) Advances recalled, i.e., where the repayment is highly doubtful and revival of the unit is not considered worthwhile and a decision has been taken to recall the advances.
 - (c) suit-filed accounts, i.e., where legal action or recovery proceedings have been initiated and suits are pending for recovery of advances.
 - (d) decreed debts, i.e., where suits have been filed and decree obtained and such decree is pending for execution.
 - (e) Debts recoverability whereof has become doubtful on account of shortfalls in value of security, difficulty in enforcing and realising the securities, or inability or unwillingness of the borrower to repay the banks dues—partly or wholly and such debts have not been included in preceding clauses (a) to (d)."

[No. 9029/F. No. 142/29/91-TPL (Part)]
AKHILESH PRASAD, Director (TPL-I)

